



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 1989/आश्विन 11, 1911

No. 187]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 1989/ASVINA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 169/आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1989

विषय :- उर्वरक (डी.ए.पी.) और उर्वरक का भारतीय बन्दरगाहों  
पर परिवहन करने के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात करने  
हेतु 600 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता (1988-89)--  
सत्सम्बन्धी लाइसेंसिंग शर्तें ।

फाइल सं. आई.पी.सी. 23/(59)/88-91 :- 1988-89 के लिए  
600 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत उर्वरक  
(डी.ए.पी.) और उर्वरक का भारतीय बन्दरगाहों पर परिवहन करने  
के लिए आवश्यक सेवाओं के आयात पर लागू होने वाली शर्तें जो इस  
सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचना के लिए अधिसूचित  
की जाती हैं ।

मेजेस्टर खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 169/आई टी सी (पी एन)  
88-91 दिनांक 3-10-89 का

परिशिष्ट

वर्ष 1988-89 के लिए छह सौ मिलियन येन (600,000,000)  
की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत उर्वरक (डी.ए.पी.)  
और उर्वरक का भारतीय परतों पर परिवहन करने के लिए  
आवश्यक सेवाओं के आयात हेतु लाइसेंसिंग शर्तें ।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1. (1) वर्ष 1988-89 के लिए 600 मिलियन येन की जापानी  
अनुदान सहायता का एम एम टी सी द्वारा उर्वरक और उसके भारतीय बन्दर-  
गाहों पर परिवहन करने के लिए आवश्यक सेवाओं के आयात हेतु जापानी  
संभरकों को उसकी वित्तीय सहायता करने के लिए किया जायेगा ।

1. (2) आयातक के नाम में आयात लाइसेंस कुल मिलाकर 660  
मिलियन येन (लगत बीमा भाड़ा) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं  
किए जाने चाहिए और उन पर एक पीरिड "1988-89" के लिए 600  
मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता" होता चाहिए । प्रथम और

द्वितीय प्रत्येक के लिए लाइसेंस को "ए/जे एन" होगा। परन्तु सामान्य छूले लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली मर्चों के लिए कोई आयात लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

1. (3) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1. (4) उर्वरक की प्राप्ति इस अनुदान के अंतर्गत जापान से ही की जाए।

1. (5) आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा आधार पर जारी किया जाएगा जोकि 31-3-1990 तक वैध रहेगा।

1. (6) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें सुपुर्दगी की अवधि के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"सुपुर्दगी 15-3-1990 तक पूर्ण की जानी है।"

1. (7) संविदा का मूल्य लागत और भाड़ा या जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य आधार पर येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन की भिन्न को हटाया जाना चाहिए) और यदि कोई हो तो भारतीय अधिकर्ता का कमीशन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यंत निःशुल्क लागत और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रवर्णित की जानी चाहिए, परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक पर वेय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त येन धनराशि होगी।

1. (8) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रिकों या जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी वैध व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए। एक प्रमाण-पत्र (दो प्रतियों में) जिसमें संभरक की पात्रता दर्शायी गई हो प्रत्येक संविदा के साथ जोड़ी जानी चाहिए।

अण्ड-2 संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :—

2. (1) 1988-89 के लिए 600 मिलियन येन की अनुदान सहायता से संबंध इस संविदा की व्यवस्था 8 मई, 1989 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2. (2) विदेशी संभरकों को भुगतान उग भुगतान के लिए "प्राधिकार पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1988-89 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, इण्डियन प्रायल भवन 5 वां तल बी.बिंग, जनपथ, नई दिल्ली, 11000 द्वारा जारी किया जाएगा।

2. (3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सतुल्य हैं जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

2. (4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के साथ विचार विमर्श करके पोत लदान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया हो और इस उद्देश्य से वह शामिल माल की डिलीवरी के कार्यक्रम के बारे में भारतीय दूतावास टोकियो को सूचित करता रहेगा और कम से कम छः हफ्ते पहले अपेक्षित पोतलदान की अधिसूचना भारतीय दूतावास को देगा ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके। अपवाद स्वरूप अगर आयातकर्ता या

तो नोटिस की इन अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातकर्ता को कबन द्वारा आवश्यक ब्यौरे की सूचना के लिए देने भी सहमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जाएगी।

अण्ड-3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन

3. (1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियों या जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियाँ सहित सभी प्रकार से पूर्ण फाँटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र में "ए पी जारी करने के आवेदन" की दो प्रतियों सहित अवर सचिव (टी ए) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संगोधानों के लिए भी लागू होगी।

3. (2) वित्त मंत्रालय (डी ई ए) जापान अनुभाग 1988-89 के लिए 600 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तबान देने के लिए संविदा की दो प्रतियाँ जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3. (3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक, जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय इण्डियन प्रायल भवन 5 वां तल बी.बिंग जनपथ नई दिल्ली-110001 को देगा जोकि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को अनुबंध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियाँ भारत का दूतावास टोकियो, आयातक भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3. (4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक ऑफ इंडिया टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देने हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

3. (5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरो के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने बैंकरो के माध्यम से रिहा करेगा।

3. (6) जापानी संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को देय बैंकिंग प्रसारों का भुगतान भारत में आयातकर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक मूत्री के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को धन परेषण द्वारा तय किया जाएगा।

अण्ड-4 रुपया निक्षेप करने के लिए उस्तदारित्व

4. (1) मूल पराक्राम्य पोत परिवहन दस्तावेज बैंक ऑफ इंडिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंधित बैंक को भेजे जाएंगे जोकि भारतीय स्टेट बैंक या अनुबंध -1 में (ग) पर यथाउल्लिखित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी जो संबंधित आयातक को पराक्राम्य जहाज-राशि दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात की मुनिश्चिन करेगा कि जापानी संभरक को भुकाई गई येन भुगतान की समस्तुय रुपये

धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहाँ देने योग्य है, व्याज के प्रभारों सहित मुख्य अदायगी की राशि सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धन राशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपये जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से द्रिबाव लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 और 35 आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 26-8-83 की शर्तों के अनुसार सरकारी लेखों में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखों में रुपया जमा किया जाता है, देय है, देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 230-17 सी (पी एन)/85-88, दिनांक 20-7-87 द्वारा संगोहित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 आयातक द्वारा किए जाने वाले रुपये निक्षेपों को निकटतम रुपये में गिना जाएगा। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस संबंध में और व्याज की दर के संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वे धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक को जिम्मेदारी होगी कि वे धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से सुरक्षित जमा कर दी है भले ही अब वे विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं। यदि आयातक सरकार को वे धनराशि के माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बंध कर दिया जाए। जिस लेख शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपॉजिट्स एण्ड एडवाइज-843 मिश्रित डिपॉजिट्स-डिपॉजिट्स फ़ार परफ़ेजिज प्रब्लेम्स एंडाउंड ग्रैंडर ग्रांट एंड फॉर्म दि गवर्नमेंट ऑफ़ जापान फ़ार 1988-89" फ़ार दि परफ़ेजिज आफ़ फ़ार्टिलाइजर्स/मिक्स बाई दि एम. एम टी सी.।

4(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ़ इंडिया, तीस हज़ारी, दिल्ली में ख़ाली के ऊपर बाहिनी और कोने में कोड़ सं. 5130000009 का संकेत देने हुए या ऐसा संभव न हो तो पैसा भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी अनुपंगी शाखा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (डालर) से डिमाण्ड ड्राफ़्ट लेकर उसे भारतीय स्टेट बैंक, तीस हज़ारी, दिल्ली-6 (ड्रायो एण्ड पेसी) को भेजा किया जाए लिखकर सरकार को साख़ से सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथानिर्धारित रूप में जमा होना चाहिए।

4(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसा किया जाने के बाद माल दिनों के भीतर भारत में संबंध बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अनिश्चित धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा। जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। ख़ाली के विभिन्न कालों को भरने समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना ख़ाली के काल में "धन परेषण" और प्राधिकारी (यदि

कोई हो) के पूर्ण व्योरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। ख़जाना ख़ाली में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :-

- (क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक।
- (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।
- (ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।
- (घ) भेजा किए गए व्याज की राशि और अवधि जिनके लिए गिना गया है।
- (ङ) कुल जमा राशि।

(व्याज की गणना जापानी संभरक को अदायगी की तारीख से और उस तारीख तक जिस तारीख को समकक्ष रुपया सरकारी खाते में जमा कराया है, की जाएगी)।

उसके पश्चात् सी.ए.ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार का संदर्भ देने हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संयोजन करने हुए ख़जाना ख़ाली रुपया जमा करने का साक्ष्य देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी.ए.ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी : भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि उसके तत्काल बाद सी.ए.ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में संबंध भारतीय बैंक की लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, यम्बई को भेजना चाहिए।

#### खण्ड-5 विधि व्यवस्थाएँ

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग करने की रिपोर्ट संभरक को की जाने वाली अदायगियों की राशि और तारीख का सुनिश्चित करने के लिए आयातक को अलग से व्यवस्था करनी होगी आयातक के बैंक द्वारा वेर या विलम्ब से प्राप्त पोत परिवहन दस्तावेज प्रलेखों की प्राप्ति के रुपया निक्षेप राशि पर देय व्याज राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से माफ़ करने का कारण नहीं माना जाएगा।

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख़पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, इंडियन आयल भवन, 5 वा तल (बी. ब्रिग) जनपथ, नई दिल्ली-11001 को भेजनी चाहिए।

5(2) आयातक को उन किसी (विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो इस अनुदान सहायता के अंतर्गत माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालते हैं।

5(3) विवाद :- यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय स्टेट बैंक टोकियो द्वारा किए गए भुगतान में पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-1 में "भुगतान की शर्तों" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों के विवाद निपटान से संबंध व्यवस्थाएँ शामिल होनी चाहिए।

5(4) भावी अनुदेश :- जापान से 1988-89 के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित या जापान से इस अनुदान सहायता के अंतर्गत सभी आचार्यों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निर्देशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन - उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

5(6) अनुबंधों की सूची -

अनुबंध - 1 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध

अनुबंध - 2 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

अनुबंध-1

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र संख्या-----

सेवा में,

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,  
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,  
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :- 600 मिलियन येन की 1988-89 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत उर्वरक और उर्वरक का भारतीय बबरगाहों पर परिवहन करने के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपर्युक्त उपस्कर के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरा भेजते हैं। जिससे कि आप संबंध जापानी सभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें।

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और जब तक यह वैध है।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित हैं। हम मामलों में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या निविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का सक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) निविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)।

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमीशन की मनराशि (येन में)।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र को आवश्यकता है।

(झ) जापानी सभरकों के साथ की गई निविदा की संख्या और दिनांक।

(ञ) जापानी सभरक का नाम और पता।

(ट) बैंक भुगतान और सभाजित तिथि जिनकी निविदाओं के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्यक्ष तिथियां।

(ड) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करने समय प्रस्तुत। किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान वसति हुए)।

(ढ) पोतलवान अनुदेश (अनुप्रेष या गैर अनुप्रेष काहनास्तरण/आंशिक पोतलवान निर्दिष्ट कोजिए)।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(त) बैंक आफ इंडिया, टोकियो के प्रभार कौन वहन करेगा कृपया, निर्दिष्ट करे।

(थ) आयातक द्वारा बचनबद्धता - "हम एतद्वारा बचन देते हैं कि हम विदेशी सभरक को देय घन राशि के समतुल्य रुपये की पूर्ण घन राशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और क्लिप्त दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने में पूर्ण राशि शोध ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी राष्ट्रों को सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी सभरक के संग्रह कोजक अनुमोदित किये जाते हैं और सभरक को भुगतान विषय, ज्ञात है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी।

अनुबंध 2

प्राधिकार पत्र सं -----

संख्या एक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली दिनांक

सेवा में

बैंक आफ इंडिया,  
टोकियो शाखा,  
टोकियो (जापान)

विषय - 600 मिलियन येन की 1988-89 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत उर्वरक और उर्वरक का भारतीय बबरगाहों पर परिवहन करने के लिए आवश्यक सेवाओं का आयात। प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 27-11-1982 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा सलग्न ब्यौरे के अनुसार खसरी-----को-----येन घनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2 कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में सभरकों को सूचना दे और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय की पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतिक लवान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने समय (आयातक के बैंक का नाम और पता)-----मूल पोतपरिवहन दस्तावेज जिसके साथ अतिरिक्त दस्तावेजों का पूरा सैट संभरक का अदायगी के लिए नाम बोजक की प्रति जगमें अदायगी यदि कोई हो भेजी जानी चाहिए।
5. आयातक द्वारा आपको संभरको एवं बैंकों के प्रभार को भेजने आदि के लिए भाड़े सहित भुगतान किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक के द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।
6. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में हम मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जाने चाहिए।
7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संप्रेषण जारी नहीं किया जा सकता है।
8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र-----तक वैध रहेगा।
9. हम अधिकार पत्र के शीर्ष पर दिया गया है इसे संविदा से संबंधित सारे पत्राचार में और बोजक में अदायगी दर्शाते हुए भी इसे लिखा जाए।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. आयातक-----को उसके पत्र सं-----दिनांक के-----के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरो से विनियमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकों के माध्यम से रुपये निक्षेप आदि जमा करने का प्रबंध करें। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पतन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बोजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाए, निक्षेप कर दिए जाएं। निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में यथाउल्लिखित आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

2. आयातक के बैंकर -----। (1) यह प्राधिकार पत्र येन ऐडिट के अंतर्गत आयातों को शामिल करने वाली संबंधित लाइसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है। लाइसेंस शर्तों और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं को देखें और आयात/विदेशी भुगतान करने समय उचित कार्रवाई करें।

(2) उनसे निर्देशन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो आच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी। प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर से और इससे अधिक के लिए 18% वार्षिक दर से ब्याज जो कि संभरक को भुगतान की तारीख बैंक/आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की तारीख और जिस तारीख को समतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाए उन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए सगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 10-8-83 और सार्वजनिक सूचना सं. 35-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 28-8-83 के अनुसार भारत सरकार के लेखों में जमा कराना है। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय है अर्थात् यह तारीख जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और यह भी तारीख जिसको भारत सरकार लेखों में रुपया जमा कराया जाता है (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा)। 20-7-87 को सार्वजनिक सूचना सं. 230आई टी सी (पी एन)/85 88 की शर्तानुसार आयातक द्वारा निक्षेप किए जाने वाले रुपये की गणना निकटतम रुपये के गुणक में की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

(3) वे धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 103 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 से दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। यह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांस-843-निषिद्ध डिपोजिट्स जिस पर ब्याज नहीं होगा डिपोजिट्स फार परचेजिंग एरसेटो अक्वोड परचेजिंग अण्डर ग्रांट ऐंड फ्राम दी गवर्नमेंट आफ जापान फार. 1988-89 अंडर डिटेल् हैड 600 मिलियन येन ग्रांट ऐंड फार परचेजिंग ग्राफ फर्टिलाइजर सर्विसेस आई टी एन.एम टी.सी.।

(4) जिन मामलों में मुख्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान की मूल रूप से एक प्रतिलिपि उन के द्वारा निम्न-लिखित पते पर भेजी जाए, जिसके साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा में प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रपत्र होना चाहिए:-

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)  
इंडियन आयल भवन, 5वां तल, (बी. विंग)  
जनपथ, नई दिल्ली 110001.

(5) जिन मामलों में मुख्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में जमा किए गए मुख्य रुपये का पूरा ब्योरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

(6) संभरक को भुगतान करने की तिथि और ओ.ई.सी.एफ द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी अदायगी की तिथि के बीच की अवधि के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो का देय ब्याज प्रभार बैंक सूत्रों के माध्यम से भारत सरकार के लेखों पर प्रभार वाले बिना बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ आपके द्वारा सीधे निपटाए जाएंगे।

(7) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के रूप में बैंक के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को आर.बी.आई.के विभिन्न परिपत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस संबंध में 18-6-1977 के ए.डी. परिपत्र सं. 22 की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. भारतीय दूतावास, टोकियो।

4. अथर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को आई.टी.सी. सं.-----दिनांक-----के संदर्भ में।

(लेखा अधिकारी)

## MINISTRY OF COMMERCE

## IMPORT TRADE CONTROL

## PUBLIC NOTICE NO. 169 ITC (PN) 88-91

New Delhi, the 3rd October, 1989

Subject :—Japanese Grant Aid of Yen 600 million (1988-89) for import of Fertilizer (DAP) and Services necessary for the transportation of the Fertilizer to ports in India—Licensing conditions—regarding.

File No. IPG/23 (59) 88-91.—The terms and conditions governing import of Fertilizer (DAP), and services for the transportation of the Fertilizer to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1988-89 of Yen six hundred million as given in Appendix to this Public Notice are hereby modified for information.

TEJENDRA KHANNA,

Chief Controller of Imports &amp; Exports

## APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 169-ITC (PN) 88-91  
dt. 3-10-89

Licensing Conditions for import of Fertilizer (DAP), and services necessary for the transportation of the Fertilizer to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1988-89 of Yen Six hundred million (Yen 600,000,000).

## Section I General Conditions

I (i) The Japanese Grant Aid for 1988-89 of Yen 600 million is intended to be used for financing payments to Japanese suppliers for import of Fertiliser and services necessary for the transportation thereof to ports in India, by the MMTC.

I (ii) The import license should be issued for an aggregate amount not exceeding Yen 660 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 600 million Japanese Grant Aid for 1988-89". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". But no import licence is required for items covered under O. G. L.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The Fertilizer should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I (v) The import licences will be issued on CIF basis with validity upto 31-3-1990.

I (vi) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1990".

I (vii) The contract value (FOB or C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of yen should be omitted) and should exclude Indian Agents Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I (viii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese juridical persons controlled by Japanese nationals. A certificate (in duplicate) showing the eligibility of the supplier should be added to each contract.

Section II The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 8th May, 1989, between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 600 million for 1988-89 and will be subject to the approval of both the Governments.

II (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Indian Oil Bhavan, Vth Floor, (B Wing), Janpath, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1988-89.

II (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II (iv) These Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

## Section III Contract Approval by Governments of India and Japan.

III (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (T.A.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance North Block, New Delhi 5 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order of confirmation in writing by the

Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1988-89 of Yen 600 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Indian Oil Bhavan, Vth Floor, B-Wing, Janpath, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

III (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

#### Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV (i) The Original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure-I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12% per annum for the first thirty days and at 18% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date

of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83 and No. 35/ITC(PN) 83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposit is made into also the day on which rupee deposit is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. NI 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. In terms of Public Notice No. 230-17C(PN)/85-88 dt. 20-7-87. The rupee deposits to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further "A/P" to him may be stopped. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances 8443-Civil Deposits-Deposits not bearing interest abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan" for 1988-89 Grant for purchase of Fertilizer services by the MMTC.

IV (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

IV (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is

invariably indicated in the columns "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and Date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the Japanese supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAAA indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents

**Note :** Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

#### Section V : Miscellaneous provisions

##### V(i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importers should make separate arrangements to as-certain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping documents etc by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Indian Oil Bhavan, Vth Floor, (B Wing), Janpath, New Delhi-110 001.

V(ii) The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

##### V(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo

must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

##### V(iv) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1988-89 from Japan.

##### V(v) Breach or violation

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the imports and Exports (Control) Act.

##### V(vi) List of Annexure :

Annexure I :—Request for issue of A/P

Annexure II :—Form of A/P.

#### Annexure-I

#### REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY

NO.

To,

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, Ist Floor,  
Parliament Street, New Delhi-110001.

**Subject :**—Import of Fertilizer and services necessary for the transportation of the fertilizer to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 600 million for 1988-89.

Sir,

In connection with the import of Fertilizer and services necessary for its transportation of the Fertilizer from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue with A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned :—

- (a) Name and address of Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.



- (h) Net C&E value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Number and date of the contract with Japanese Suppliers.
- (j) Name and address of the Japanese Supplier
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/part shipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's bank in India.
- (p) Who will bear the banking charges of the B. O. I., Tokyo-importer or supplier, please specify.
- (q) Undertaking by the importer :—"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of Payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to suppliers".

Yours faithfully,

Annexure-11.

Authorisation to Pay No.

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To,

The Bank of India,  
Tokyo Branch,  
Tokyo (Japan).

Subject :—Import of Fertilizer and services necessary for the transportation of the fertilizer to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 600 million for 1988-89. Issue of Authorisation to Pay.

Dear, Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 27-11-1982 entered into with

your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen \_\_\_\_\_ to M/s. \_\_\_\_\_ as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P may be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to \_\_\_\_\_ (Name & Address of importers' Banker) the original shipping documents (negotiable as well as additional complete set of the documents and copy the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. Banking charges including charges for handling document and charges of overseas Suppliers, Bankers if any, payable to you by the importers, will be settled directly by the importer's bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importers' bank.

7. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific Authority from this Ministry.

8. This A/P will remain valid upto \_\_\_\_\_.

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,

Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer \_\_\_\_\_ with reference to their Letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_. They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the licensing conditions.

2. Importers' Banker \_\_\_\_\_.

(i) This Authorisation to Pay is issued under the relevant Licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices/order etc. may be referred to

and appropriate action taken concerning the import foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of the documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government of India's account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-1983 and No. 35-ITC(PN)/83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the date on which rupee deposit is made into the Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). In terms of Public Notice No. 230-17C(PN)/85-88 dt. 20-7-87 the rupee deposits to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import negotiable documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is K-Deposits & Advances-8443-CIVIL Deposits-Deposit not bearing interest Deposit for purchases etc.

abroad-purchases under Grant Aid from Govt. of Japan' for 1988 89 under detailed head "Yen 600 million grant aid for purchases of fertilizer|services by the MMTC".

(iv) One copy of the Challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Indian Oil Bhavan, Vth Floor, (B Wing), Janpath, New Delhi-110 001.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968, mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the B.O.I., Tokyo.

(vii) The Bank's duties and responsibilities as authorised Dealer in foreign exchange are prescribed in various AD Circulars of the R.B.I. Specific reference in this regard is invited to A.D. Circular No. 22 dated 18-6-1977.

3. Embassy of India, Tokyo.

4. The Under Secretary (Japan Section), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi with reference to I.D. No. \_\_\_\_\_ dt. \_\_\_\_\_

( )

Accounts Officer.

## MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 170—ITC(PN)/88—91

New Delhi, the 6th October, 1989

Subject: Import and Export Policy for April 1988—March 1991.

F.No. IPC/4/5(340)/85—88:—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1988—March, 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC(PN)/88—91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1988—91 (Volume I)	Reference	Amendment				
1	2	3	4				
1.	135 (132)	Appendix 3 Part—A Entry No. 216A 'Glass Epoxy Laminates'	This entry shall be deleted.				
2.	149 (145)	Appendix 3 Part—A Entry No. 637 Sub-entry No. (1/)	The description of this sub-entry shall be amended to read as under: “(16) Phenolic/phenolic paper based copper clad laminates/ Glase Epoxy Laminates.”				
3.	161 (158)	Appendix 5 Part—B	After the existing Item No. 10, the following shall be added:— “Phosphoric Acid and Ammonia.  11. In the case of Phosphoric Acid and Ammonia, import will be made only by the State Trading Corporation of India (STC) under Open General Licence on the basis of foreign exchange released by the Government in its favour. Imports, distribution and pricing will be made by the STC as per the connected policy of the Government in the Department of Fertilisers.”				
4.	166 (164)	Appendix 6 Import of items under Open General Licence	After the existing Item No. 48, the following new item shall be added:— <table><tr><th>Item</th><th>Categories of eligible importers</th></tr><tr><td>“49. Audio-Visual News or Audio-visual Views material including News Clippings</td><td>Actual Users as certified by the Union Ministry of Information &amp; Broadcasting.”</td></tr></table>	Item	Categories of eligible importers	“49. Audio-Visual News or Audio-visual Views material including News Clippings	Actual Users as certified by the Union Ministry of Information & Broadcasting.”
Item	Categories of eligible importers						
“49. Audio-Visual News or Audio-visual Views material including News Clippings	Actual Users as certified by the Union Ministry of Information & Broadcasting.”						